RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 31 जनवरी से 06 फरवरी 2026 भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष- 13 अंक-77 पृष्ठ- 8 मूल्य- रु. 5 /-

भारत-US व्यापार समझौता ऑटो कंपोनेंट्स की प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा: ACMA

टैरिफ में कमी से निर्यात को नई गति, 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त अवसर; ACMA ने सरकार से तेजी से समझौते की अपील की

नई दिल्ली: ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते (FTA) से ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफी बढ़ोतरी होगी। ACMA के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने कहा, अमेरिका में भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स पर 2.5% से 25% तक का टैरिफ है। समझौते से यह टैरिफ शून्य या न्यूनतम हो जाएगा, जिससे हमारा निर्यात 10 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।

अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट निर्यात बाजार है, जहां 2025 में 5 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ। ACMA का अनुमान है कि टैरिफ कटौती से भारतीय कंपनियां चीन, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकेंगी। खासकर इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और EV पार्ट्स में बड़ा फायदा होगा।

अग्रवाल ने कहा, यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम के साथ मिलकर ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देगा। हमने सरकार से वार्ता में तेजी लाने और ऑटो सेक्टर को प्राथमिकता देने की अपील की है। भारत का ऑटो कंपोनेंट निर्यात FY25 में 20% बढ़कर 18.5 अरब डॉलर हो गया, और 2030 तक 50 अरब डॉलर का लक्ष्य है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-US FTA से छोटे-मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी फायदा होगा, जो सेक्टर का 60% हिस्सा हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। ACMA ने कहा कि समझौते में नियमों का पालन और IPR सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। यह कदम भारत को वैश्विक ऑटो हब बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

अनारॉक–फिक्की रिपोर्ट: 2030 तक 2400+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से 28 लाख नई नौकरियां

भारत ग्लोबल टैलेंट हब बनेगा, IT, फिनटेक और हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा रोजगार; GCC से 1.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक योगदान

नई दिल्ली: अनारॉक और फिक्की की नई रिपोर्ट ने भारत के रोजगार परिदृश्य में बड़ा उछाल आने की भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में 2400 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित हो जाएंगे, जो 28 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करेंगे। वर्तमान में भारत में लगभग 1600 GCC हैं, जो 18 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत GCC के लिए वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। IT, फिनटेक, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। 2030 तक GCC सेक्टर का आर्थिक योगदान 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। अनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, "भारत की कुशल युवा शक्ति, डिजिटल इंफ्रा और लागत लाभ से GCC का तेज विस्तार हो रहा है। यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा।"

GCC कंपनियां उच्च वेतन, बेहतर सुविधाएं और ग्लोबल एक्सपोजर देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 70% GCC बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में केंद्रित हैं, लेकिन अब टियर-2 शहरों जैसे इंदौर, कोच्चि और जयपुर में भी विस्तार हो रहा है। फिक्की के एक अधिकारी ने कहा, GCC से न केवल नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा।"

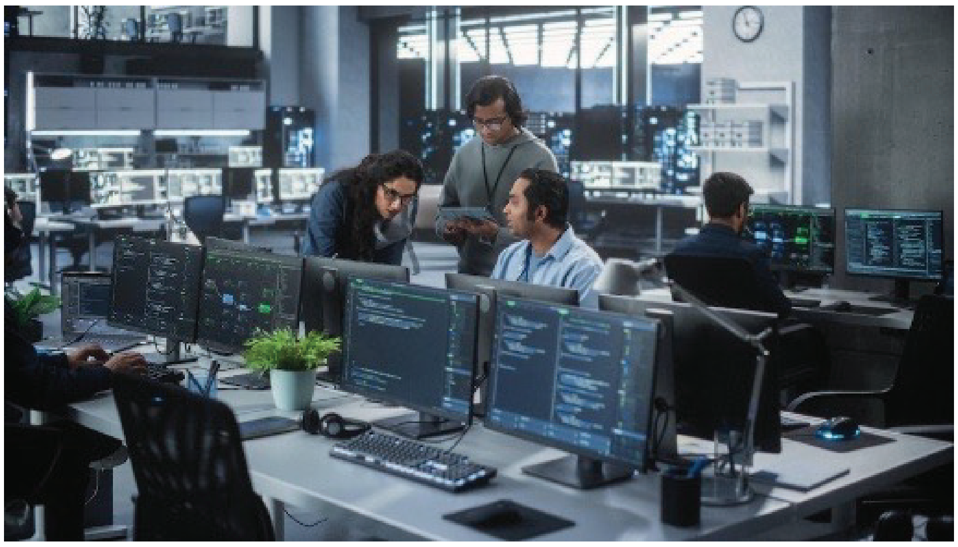

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा GCC हब बन सकता है। यह विकास युवाओं के लिए बेहतर करियर और उच्च आय का अवसर लाएगा। रिपोर्ट में सरकार से स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रा और टैक्स प्रोत्साहन बढ़ाने की अपील की गई है।

बजट 2026: कुछ सामान महंगे, कुछ सस्ते – जानिए क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ

जीएसटी में बदलाव से घरेलू बजट पर असर, मोबाइल-लैपटॉप सस्ते, सिगरेट-कॉस्मेटिक्स महंगे; मध्यम वर्ग को राहत और चुनौती दोनों

भोपाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2026-27 में जीएसटी दरों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे कई रोजमर्रा के सामान सस्ते तो कुछ महंगे हो गए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

क्या सस्ता हुआ?

- मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट पर जीएसटी अब 18% रह गया है (पहले 28%)। इससे इनकी कीमतें 8-12% तक कम हो सकती हैं।
- छोटे कारों (1.2 लीटर से कम इंजन) पर जीएसटी 18% हो गया है, जिससे छोटे परिवारों को राहत मिलेगी।
- कुछ घरेलू उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन (1.2 लीटर से कम) और मिक्सर ग्राइंडर पर भी जीएसटी कम हुआ है।
- हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी 12% रह गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा।

क्या महंगा हुआ?

- सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और पान मसाला पर जीएसटी 28% से बढ़कर 32% हो गया है।
- कुछ कॉस्मेटिक्स, पर्फ्यूम और हेयर डाई पर जीएसटी बढ़ा है।
- प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे चॉकलेट, बिस्किट और पैकेज्ड स्नैक्स पर जीएसटी में मामूली बढ़ोतरी।
- कुछ लक्जरी आइटम्स जैसे हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ये बदलाव आम आदमी को राहत देने और राजस्व बढ़ाने के लिए संतुलित तरीके से किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल-लैपटॉप सस्ते होने से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन तंबाकू और लग्जरी सामान महंगे होने से मध्यम वर्ग पर असर पड़ेगा। बजट में जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर अमल से बाजार में कीमतें जल्द बदल सकती हैं।

US Startup Sets Sights on Real-World AI Applications in IndiaNew Launches

Anthropic and Other Innovators Target India's Diverse Use Cases; Focus on Agriculture, Healthcare, and Vernacular AI to Drive Adoption

Bengaluru: A leading US-based AI startup is intensifying its push into India, aiming to deploy real-world artificial intelligence applications tailored to the country's unique challenges and opportunities. The company, which has already gained global attention for its advanced large language models, sees India as a critical market for scaling practical AI solutions beyond research and chat interfaces.

India's massive digital population, growing smartphone penetration, and diverse linguistic landscape make it an ideal testing ground for AI that solves everyday problems. The startup plans to focus on high-impact sectors such as agriculture (crop advisory and yield prediction using satellite and local data), healthcare (AI-assisted diagnostics in low-resource settings), and education (vernacular tutoring tools for regional languages).

India offers unparalleled scale and diversity of real-world use cases. We are building AI that speaks local languages, understands regional contexts, and delivers value to millions of small farmers, small businesses, and students, a senior executive from the startup said during a recent visit to Bengaluru.

The company is partnering with Indian tech firms, universities, and government bodies to co-develop solutions compliant with local data privacy laws and cultural nuances. It is also investing in vernacular datasets and low-bandwidth AI models to ensure accessibility in rural areas with limited internet.

Industry experts view this move as part of a broader trend where global AI leaders are shifting focus from consumer chatbots to enterprise and societal applications in emerging markets. India's startup ecosystem, government initiatives like India AI Mission, and the rapid growth of digital infrastructure are key enablers.

With India's AI market projected to reach $17 billion by 2027, the startup's real-world focus could accelerate adoption, create jobs, and address critical development challenges. The entry signals growing confidence in India as not just a consumer of AI, but a co-creator of impactful, inclusive technology.

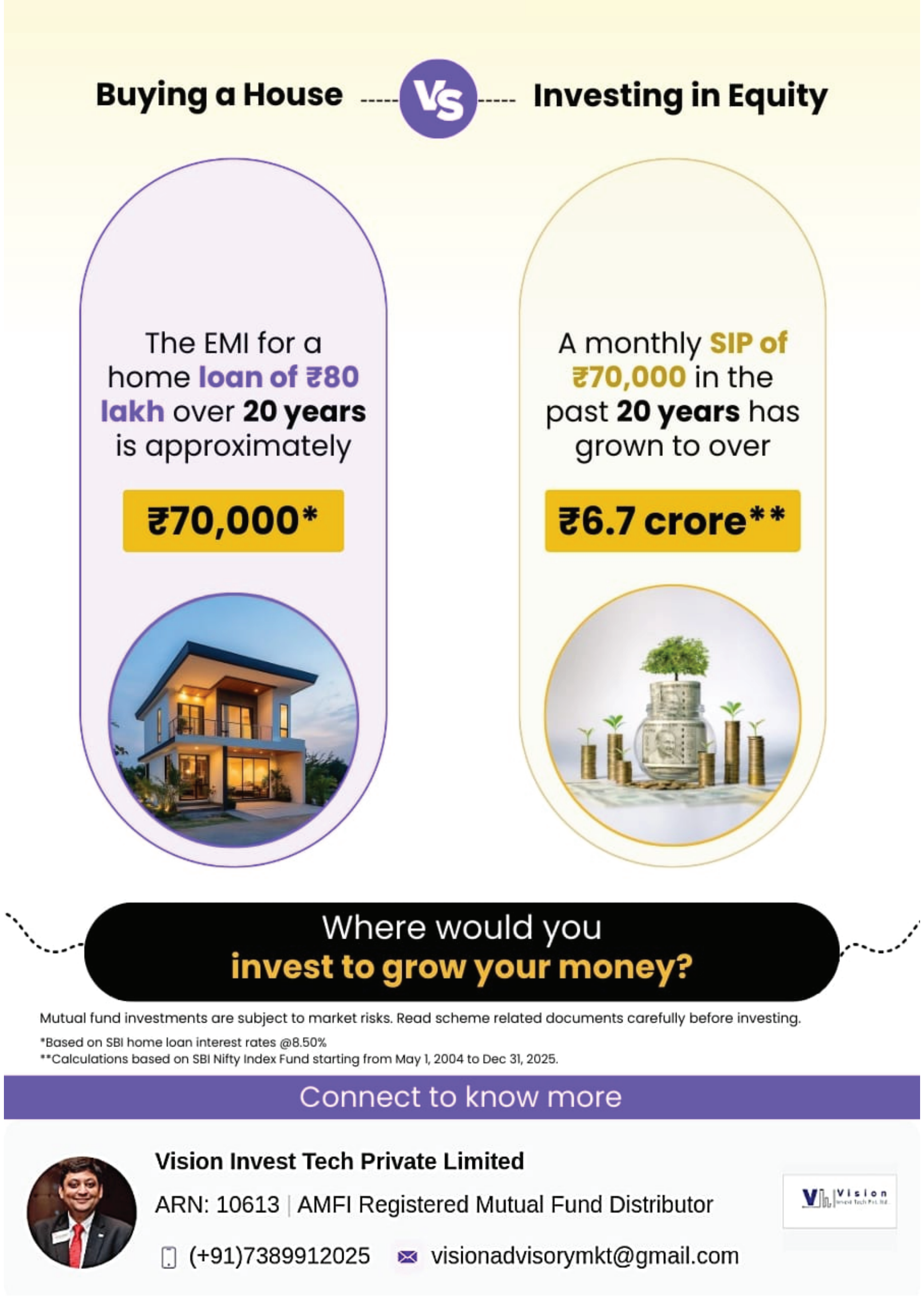

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Budget 2026 and India–US Deal: Setting the Stage for India’s Next Growth Phase

India’s economic journey is entering an important phase as Budget 2026 and the strengthening India–US strategic partnership together create new growth opportunities. Both developments are expected to influence investment, trade, employment, technology transfer, and overall economic expansion. Experts believe that the combined impact of domestic policy reforms and global collaboration can accelerate India’s journey toward becoming a developed economy.

Budget 2026 has focused on maintaining a balance between growth, fiscal discipline, and social development. The government has continued to prioritise infrastructure spending, manufacturing promotion, and digital expansion. Increased allocation toward roads, railways, logistics, defence production, and renewable energy is expected to create jobs and improve business efficiency. Infrastructure investment has a multiplier effect because it supports multiple sectors such as cement, steel, construction, and transportation. This creates demand across industries and strengthens economic momentum.

Another key highlight of Budget 2026 is the push toward manufacturing and ‘Make in India’ initiatives. Production-linked incentive (PLI) schemes and incentives for domestic manufacturing aim to reduce import dependence and increase exports. (These steps support India’s ambition to become a global manufacturing hub, especially in sectors like electronics, defence equipment, semiconductors, and green energy.

At the same time, the growing India–US partnership is opening new doors for trade and technology exchange. The United States is India’s largest trading partner, with bilateral trade crossing $190 billion in recent years. The two countries are working closely in areas such as defence technology, semiconductor manufacturing, artificial intelligence, clean energy, and digital infrastructure. Increased cooperation in these high-value sectors can attract foreign investment and strengthen India’s technological capabilities.

One of the biggest benefits of the India–US deal is the potential boost to supply chain diversification. Many global companies are looking to reduce their dependence on a single manufacturing destination. India is emerging as a preferred alternative due to its large workforce, improving infrastructure, and stable policy environment. Budget 2026 complements this trend by offering incentives for global companies to establish manufacturing facilities in India.

The defence sector is another major area where both developments are working together. The government’s focus on defence indigenisation, combined with technology collaboration with the US, can help Indian companies move up the value chain. Increased domestic defence production not only improves national security but also creates export opportunities and skilled employment.

The renewable energy sector is also expected to gain from this combined push. India has set ambitious targets for clean energy expansion, and collaboration with the US in green hydrogen, solar technology, and battery storage can accelerate these goals. Budgetary support for renewable infrastructure further strengthens India’s commitment to sustainable growth.

Financial markets have responded positively to both developments. Investors view policy continuity, infrastructure spending, and global partnerships as signals of long-term economic stability. Sectors such as capital goods, defence, renewable energy, manufacturing, and banking are expected to benefit from increased investment and credit demand.

However, challenges remain. Global economic slowdown, geopolitical tensions, and inflation risks could affect trade and capital flows. To sustain growth momentum, India must continue structural reforms, maintain fiscal discipline, and improve ease of doing business.

In conclusion, Budget 2026, and the India–US partnership together represents a powerful combination for economic transformation. While the budget strengthens domestic growth through infrastructure and manufacturing, the strategic alliance with the US brings technology, investment, and global market access. If implemented effectively, these developments can set the foundation for India’s next growth phase and move the country closer to its long-term development vision.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

UPI ट्रांजेक्शन दिसंबर 2025 तक 230 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर: सरकार

वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 18 अरब से अधिक ट्रांजेक्शन, 25% की वार्षिक वृद्धि; डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता

नई दिल्ली: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक 230 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड मूल्य के ट्रांजेक्शन के साथ नई ऊंचाई छू चुका है। सरकार ने मंगलवार को यह आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि यह भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 तक UPI पर 18 अरब से अधिक ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 25% अधिक है।

UPI के दैनिक औसत ट्रांजेक्शन दिसंबर में 60 करोड़ से अधिक रहे, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दिसंबर 2025 में अकेले 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मूल्य ट्रांसफर हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, UPI ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाकर वैश्विक मिसाल कायम की है। यह छोटे व्यापारियों, ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ है।

UPI की सफलता का श्रेय सरकारी नीतियों, NPCI की तकनीकी मजबूती और बैंकों-फिनटेक कंपनियों के सहयोग को दिया जा रहा है। UPI लाइट, क्रेडिट-ऑन-UPI और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स से इसकी पहुंच और बढ़ी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि FY26 के अंत तक UPI ट्रांजेक्शन मूल्य 300 लाख करोड़ रुपये पार कर सकता है।

यह उपलब्धि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 50% योगदान देने वाली UPI को और मजबूत बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से UPI का विस्तार तेज हुआ है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100% डिजिटल पेमेंट्स है। यह रिकॉर्ड 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन का प्रमाण है।

US-India Trade Deal: Tariff Cuts Reignite Export Hopes for Electronics Manufacturers

Reduced Duties on Components and Finished Goods to Boost Competitiveness; Industry Eyes $10–15 billion Additional Exports by 2030

New Delhi: The proposed US-India trade deal, featuring significant tariff reductions on electronics and components, has reignited optimism among Indian manufacturers, who see a major opportunity to expand exports to the world's largest consumer market.

According to officials from the Ministry of Commerce and Electronics and IT, the agreement currently in advanced negotiations includes slashing or eliminating duties on key categories such as semiconductors, mobile phones, laptops, chargers, and consumer electronics parts. Currently, Indian electronics face tariffs of 10–25% in the US, while competitors like Vietnam, Malaysia, and China benefit from lower or zero duties under existing trade frameworks.

The Electronics Industries Association of India (ELCINA) and India Cellular and Electronics Association (ICEA) welcomed the development, stating that tariff relief could add $10–15 billion in annual exports within five years. These levels the playing field for Indian manufacturers who have invested heavily in local production under the PLI scheme, said an ICEA spokesperson.

We expect a significant shift in global supply chains toward India.India's electronics exports crossed Rs 4 lakh crore in 2025, with mobile phones and components contributing the lion's share. The sector has grown at 30%+ CAGR in recent years, driven by Apple, Samsung, and Foxconn's expanding manufacturing footprint. Lower US tariffs would accelerate this momentum, particularly for high-value items like semiconductors and EV components.

Industry leaders emphasized the need for quick finalisation of the deal to capitalise on the current window of supply chain diversification away from China. The government is also pushing for strong rules of origin and IP protections to ensure benefits remain with Indian producers.

As India targets $300 billion in electronics manufacturing and $120 billion in exports by 2030, the US trade deal is seen as a game-changer. Shares of major electronics and component firms rose on BSE following reports of progress in negotiations, reflecting strong market optimism.

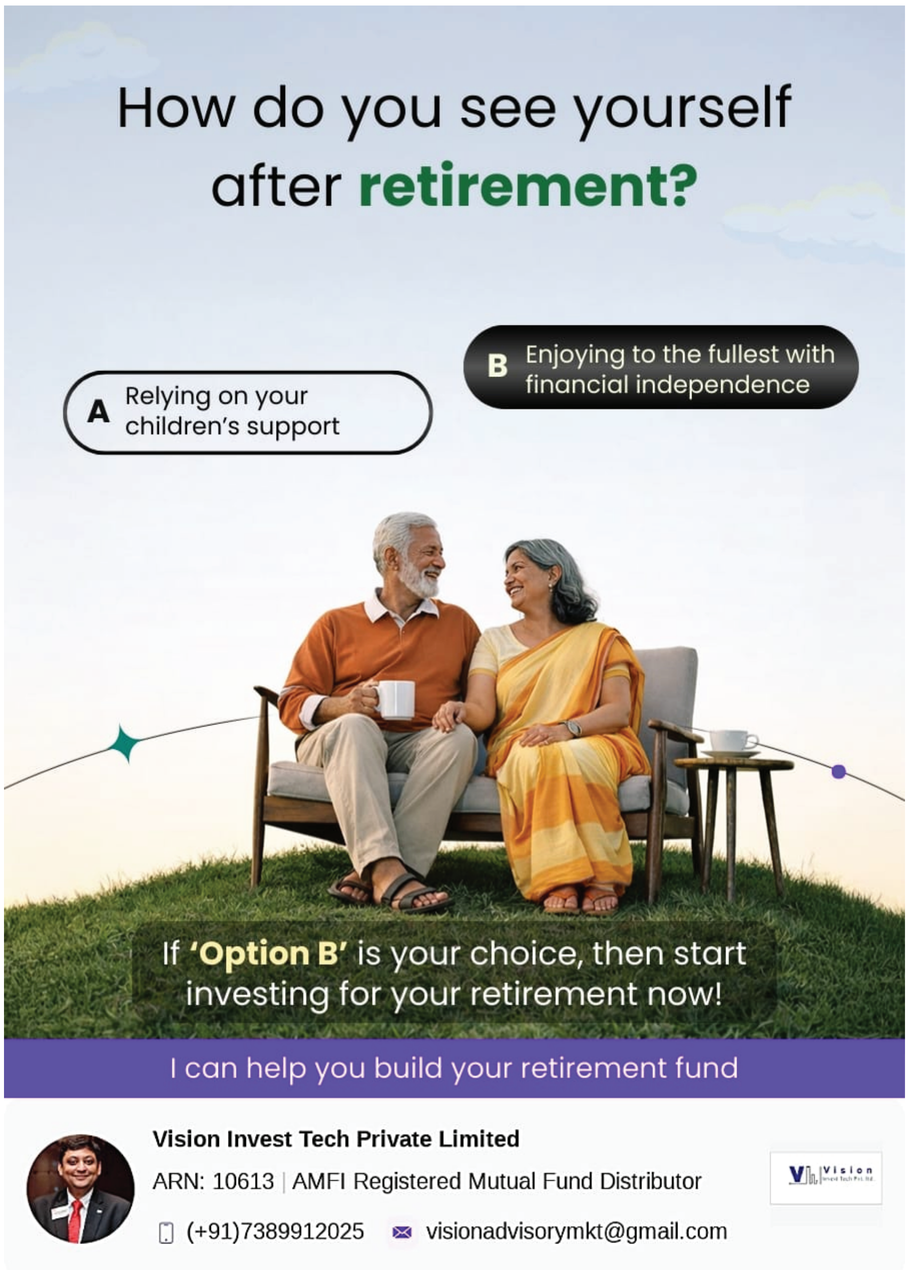

India's AWL Agri Eyes Boost in Oil and Basmati Rice Exports Amid US Tariffs

Potential Gains in US Market as Competitors Face Higher Duties; Company Sees Opportunity to Expand Share in Premium Segments

Mumbai: AWL Agri Business Ltd, a leading player in edible oils and basmati rice, is optimistic about a potential surge in exports to the United States following the imposition of higher tariffs on competing countries. The US has recently announced additional tariffs on agricultural imports from certain nations, creating a relative cost advantage for Indian products in the world's largest consumer market.

In an investor update, AWL Agri highlighted that the tariff structure could significantly benefit its edible oils (especially soybean oil and sunflower oil) and premium basmati rice segments. US tariffs on key competitors are likely to make Indian products more competitive on price and availability, the company stated. AWL Agri, part of the Adani Wilmar group, is already a major exporter of basmati rice to the Middle East, Europe, and the US, and has been expanding its edible oil refining and export capacities.

The US is one of the fastest-growing markets for Indian basmati rice, with demand driven by the growing South Asian diaspora and increasing preference for premium long-grain varieties. Similarly, edible oil imports into the US have risen sharply due to domestic supply constraints. Analysts estimate that a sustained tariff disadvantage for competitors could help Indian exporters capture an additional $300–500 million in annual shipments in these categories.

AWL Agri has been investing in backward integration, quality certifications, and supply chain efficiency to meet stringent US food safety and labelling standards. The company expects the tariff differential to support higher realisations and volume growth in the coming quarters.

Industry bodies like APEDA and SEA have welcomed the development, urging the government to fast-track negotiations to secure preferential access under any future India-US trade framework. With India's agri-exports crossing $50 billion in FY25, such strategic opportunities are critical to achieving the $100 billion export target by 2030.

KEC International Secures Rs 1,020 Crore Orders in India and Overseas

Strong Wins in Transmission & Distribution and Cables Businesses; Reinforces Order Book Momentum Amid Infrastructure and Energy Transition Push

New Delhi: : KEC International Ltd, the flagship infrastructure engineering company of the RPG Group, has bagged new orders worth Rs 1,020 crore across India and international markets. The company announced the development in a regulatory filing, with the orders spread across its Transmission & Distribution (T&D) and Cables businesses.

The T&D segment secured orders from both domestic and overseas clients for high-voltage transmission lines, substations, and turnkey projects. These include key infrastructure upgrades in India and select international markets in the Middle East and Africa. The Cables business won orders for supply of high-performance power and control cables, driven by demand from utilities, railways, and industrial clients.

This order inflow reflects our continued strength in executing complex infrastructure projects and our growing presence in global markets, said Vimal Kejriwal, Managing Director & CEO, KEC International. The company highlighted that the wins are aligned with rising investments in power transmission, renewable energy evacuation, and railway electrification in India, as well as ongoing grid modernisation in emerging economies.

KEC's order book now stands strong, providing good revenue visibility for the coming quarters. The company has been aggressively bidding for projects under India's massive power sector capex cycle and global energy transition initiatives. With a diversified presence in over 70 countries, KEC continues to benefit from its execution capabilities and strong client relationships.

Analysts expect the company to maintain 15–20% revenue growth in FY26, supported by robust order inflows and margin improvement in high-value projects.

As India accelerates its target of 500 GW non-fossil capacity by 2030 and global grids modernise, KEC's latest wins position it well to capitalise on the multi-year infrastructure upcycle in power and transportation sectors.

BPCL Goes Big on Petrochemicals, Raises Capex as IOC and ONGC Trim Budgets

Rs 50,000 Cr Investment Plan Targets Downstream Value Addition; Aims to Offset Refining Margin Pressures and Capture Higher Growth in Specialty Chemicals

Mumbai: Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) is aggressively expanding its petrochemicals footprint with a significantly higher capex outlay, even as peers IOC and ONGC have signalled cautious spending in FY26. BPCL has earmarked around Rs 50,000 crore over the next five years for petrochemical projects, including the expansion of its Bina refinery complex and new downstream units focused on specialty chemicals, polymers, and aromatics.

The move comes as refining margins remain under pressure due to global oversupply and volatile crude prices. BPCL's strategy is to shift focus from pure refining to higher-value petrochemicals, where margins are typically 2–3 times higher. The company plans to build integrated petrochemical complexes at Bina (Madhya Pradesh) and Bargarh (Odisha), targeting production of polypropylene, polyethylene, and specialty polymers.

"Petrochemicals are our future growth engine. While refining remains core, downstream integration will deliver better returns and de-risk the business," BPCL Chairman & Managing Director G. Krishnakumar said. The increased capex contrasts with IOC's moderated spending and ONGC's focus on upstream exploration amid global uncertainties.

BPCL's petrochemical push aligns with India's growing demand for polymers in packaging, automotive, and infrastructure sectors. The company expects petrochemicals to contribute 25–30% of revenues

by 2030, up from less than 10% currently. The expansion will also create thousands of direct and indirect jobs and support India's targets of 30 million tonnes of petrochemical capacity by 2030.

Analysts view BPCL's strategy positively, forecasting improved profitability despite refining headwinds. As India aims to become a global petrochemical hub, BPCL's bold capex bet signals confidence in long-term value creation amid a challenging refining cycle.

Pidilite Eyes Export Rebound After Indo-US Tariff Revision, Targets Double-Digit Volume Growth in FY27

Lower Duties to Boost Competitiveness in Adhesives & Sealants; Domestic Demand, Innovation Drive Optimism for Strong Recovery

Bhubaneswar: Pidilite Industries, India's leading manufacturer of adhesives and construction chemicals, is optimistic about a strong export rebound in the coming quarters following the proposed tariff revisions in the India-US trade negotiations. Managing Director & CEO Bharat Puri said the company expects a meaningful recovery in exports to the US market, its largest overseas destination, as reduced duties correct the current disadvantage faced by Indian products against competitors.

Speaking at the company's investor interaction, Puri highlighted that the tariff alignment would significantly improve price competitiveness for Pidilite's flagship brands like Fevicol, Dr. Fixit, and M-Seal in the US. We have been under pressure due to higher tariffs, but once the revision comes through, we anticipate a strong uptick in demand from our distributors and industrial clients in

the US, he said. Pidilite's exports, which contribute around 8-10% of revenue, had faced headwinds in recent quarters due to tariff differentials and global supply chain shifts.On the domestic front, the company remains confident of sustained double-digit volume growth in FY27, driven by steady demand in housing, infrastructure, and industrial segments. Rural recovery, rising disposable incomes, and government capex in construction are key tailwinds. Puri noted that Pidilite's focus on innovation new product launches in waterproofing, tile adhesives, and industrial sealants along with strong brand equity, will help maintain market leadership.

The company reported healthy volume growth in Q3 FY26 despite input cost pressures, with margins supported by operational efficiencies and premiumisation. Analysts expect Pidilite to deliver 12-15% revenue growth in FY27, with EBITDA margins improving to 25%+ levels.

As India targets deeper integration into global supply chains and higher exports, Pidilite's export recovery and domestic momentum position it well to capitalise on the structural growth in adhesives and construction chemicals.

बीएचईएल ने Hindalco से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोजेक्ट हासिल किया

एडिटया एल्युमिनियम प्लांट में पावर इक्विपमेंट सप्लाई, 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य; ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत सहयोग, मेक इन इंडिया को बल

नई दिल्ली: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने हिंदाल्को इंडस्ट्रीज से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। यह प्रोजेक्ट ओडिशा के लपंगा में Hindalco के एडिटया एल्युमिनियम प्लांट के विस्तार से जुड़ा है। बीएचईएल ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में बताया कि कंपनी Hindalco को पावर इक्विपमेंट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और अन्य हाई-वोल्टेज सिस्टम सप्लाई करेगी।

यह प्रोजेक्ट हिंदाल्को की स्मेल्टर क्षमता को दोगुना करने के विस्तार का हिस्सा है। बीएचईएल के चेयरमैन और एमडी एन. श्रीनिवास ने कहा, यह ऑर्डर हमारी पावर इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। हम समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।" प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

Hindalco इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनियों में से एक है और इस विस्तार से उसकी क्षमता 1 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। बीएचईएल का यह ऑर्डर उसके ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा, जो वर्तमान में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने हाल के वर्षों में रिन्यूएबल और पावर सेक्टर में कई बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा भारत के इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। इससे हजारों रोजगार सृजित होंगे और 'मेक इन इंडिया' को नई गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।

एसीएमई सोलर ने एनएचपीसी के साथ 3,700 करोड़ का FDRE प्रोजेक्ट PPA साइन किया

1,000 MW क्षमता का राउंड-द-क्लॉक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, 2027 तक कमीशनिंग; भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो लक्ष्य को नई गति

नई दिल्ली: एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) के साथ 3,700 करोड़ रुपये के फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 1,000 MW क्षमता का प्रोजेक्ट है, जो सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज के हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है। कंपनी ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी।

यह प्रोजेक्ट FDRE के तहत भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें 24x7 बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। एसीएमई सोलर के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा, यह समझौता हमारी FDRE क्षमता को 3 GW तक ले जाएगा। हम 2027 तक प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात में विकसित किया जाएगा, जहां सोलर और विंड संसाधन प्रचुर हैं।

NHPC के चेयरमैन और एमडी आर.के. वर्मा ने कहा, यह PPA देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाने और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। FDRE प्रोजेक्ट्स से राउंड-द-क्लॉक बिजली मिलेगी, जो पारंपरिक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की कमी को दूर करेगा।

यह समझौता भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल ऊर्जा लक्ष्य (2030) को मजबूती देगा। एसीएमई सोलर की कुल क्षमता अब 12 GW से अधिक हो गई है। कंपनी ने हाल ही में कई FDRE प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि FDRE भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन का भविष्य है। यह कदम भारत को ग्लोबल रिन्यूएबल लीडर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25694	26935	26638	26166	25869	25397	25100	24628
BANK NIFTY	60121	65978	63872	61996	59890	58014	55908	54032
SENSEX	83314	92131	89001	86158	83028	80185	77055	74212
FINNIFTY	27807	30506	29390	28599	27483	26692	25576	24785
MIDCAP	13645	15315	14642	14143	13470	12971	12298	11799
ACC	1673	1815	1754	1714	1653	1613	1552	1512
AXISBANK	1342	1521	1469	1406	1354	1291	1239	1176
ABCAPITAL	347	410	386	366	342	322	298	278
BHARTIARTL	2023	2231	2140	2082	1991	1933	1842	1784
BHEL	267	312	293	280	261	248	229	216
BEL	364	409	399	381	371	353	343	325
BIOCON	430	518	490	460	432	402	374	344
CDSL	1329	1579	1476	1402	1299	1225	1122	1048
DATAPATTERN	2705	3468	3152	2929	2613	2390	2074	1851
ESCORTS	3767	4282	4030	3898	3646	3514	3262	3130
EICHERMOTOR	7155	7999	7664	7409	7074	6819	6484	6229
FEDERAL BANK	287	320	309	298	287	276	265	254
GRINFRAPOJECT	982	1111	1073	1027	989	943	905	859
HDFCBANK	941	1072	1033	987	948	902	863	817
HCLTECH	1591	1929	1854	1723	1648	1517	1442	1311
HINDUNILVR	2420	2591	2510	2465	2384	2339	2258	2213
HAL	4066	5291	5001	4533	4243	3775	3485	3017
HYUNDAI	2185	2373	2312	2248	2187	2123	2062	1998
IOC	175	208	194	185	171	162	148	139
ICICIBANK	1409	1529	1473	1441	1385	1353	1297	1265
INFY	1505	1910	1819	1662	1571	1414	1323	1166
ITC	326	361	345	335	319	309	293	283
KOTAKBNK	422	452	439	430	417	408	395	386
LICHOUSING	517	576	552	535	511	494	470	453
LT	4065	4572	4347	4206	3981	3840	3615	3474
LUPIN	2162	2411	2327	2245	2161	2079	1995	1913
MARUTI	14962	16699	15990	15476	14767	14253	13544	13030
M&M	3580	4003	3823	3702	3522	3401	3221	3100
MGL	1145	1337	1251	1198	1112	1059	973	920
MAZGAONDOC	2402	2943	2801	2601	2459	2259	2117	1917
PFC	418	485	453	435	403	385	353	335
RECLTD	373	426	406	390	370	354	334	318
RELIANCE	1450	1670	1580	1515	1425	1360	1270	1205
SBIN	1066	1210	1150	1108	1048	1006	946	904
SUNPHARMA	1695	1892	1810	1753	1671	1614	1532	1475
SHRIRAMFINANCE	1001	1152	1097	1049	994	946	891	843
TITAN	4141	4534	4347	4244	4057	3954	3767	3664
TCS	2938	3654	3502	3220	3068	2786	2634	2352
TATAMOTORS	369	436	410	390	364	344	318	298
UPL	737	905	834	786	715	667	596	548
VALIENT	271	348	316	294	262	240	208	186
WIPRO	230	285	273	251	239	217	205	183

जियो स्टूडियोज ने सिख्या एंटरटेनमेंट में 50.1% हिस्सेदारी खरीदी

बॉलीवुड और ओटीटी कंटेंट में विस्तार, सिख्या के साथ मिलकर प्रीमियम वेब सीरीज और फिल्मों का लक्ष्य; रिलायंस का मनोरंजन कारोबार और मजबूत

मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीडिया और मनोरंजन इकाई जियो स्टूडियोज ने सिख्या एंटरटेनमेंट में 50.1% बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह सौदा रिलायंस के लिए भारतीय ओटीटी और फिल्म कंटेंट सेगमेंट में एक बड़ा कदम है। सिख्या एंटरटेनमेंट, जो 'द फेमिली मैन', 'पाताल लोक', 'आर्या' और 'असुर' जैसी हिट वेब सीरीज बना चुकी है, अब जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर काम करेगी।

जियो स्टूडियोज के सीईओ ने कहा, "सिख्या के साथ यह साझेदारी हमें प्रीमियम और मूल कंटेंट बनाने में नई ताकत देगी। हम भारतीय दर्शकों के लिए वैश्विक स्तर की कहानियां और सीरीज लाएंगे।" सिख्या के संस्थापक और सीईओ विक्रम मल्होत्रा ने बताया कि यह साझेदारी क्रिएटिव फ्रीडम और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी।

सिख्या एंटरटेनमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी+ हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कई सफल वेब सीरीज बनाई हैं। इस सौदे से जियो प्लेटफॉर्म्स (जियोसिनेमा) पर भी सिख्या की कंटेंट की उपलब्धता बढ़ेगी। यह कदम रिलायंस के मनोरंजन कारोबार को मजबूत करेगा, जो पहले से ही फिल्म प्रोडक्शन और स्ट्रीमिंग में सक्रिय है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिग्रहण भारतीय ओटीटी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। भारत में ओटीटी सब्सक्राइबर 2025 में 10 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। सिख्या के साथ साझेदारी से जियो को प्रीमियम कंटेंट में बढ़त मिलेगी। यह कदम भारतीय मनोरंजन उद्योग में नए अध्याय की शुरुआत है।

Jio STUDIOS | SIKHYA ENTERTAINMENT

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in